भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
19.03.2021 के
तारांकित प्रश्न सं. 258 का उत्तर

रेलवे पर परोक्ष रूप से अश्रित व्यक्तियों पर
वैश्विक महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव

***258 डा. सांतनु सेनः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मार्च में लॉकडाउन के पश्चात् से विशेष रूप से अपनी आजीविका के लिए रेलवे पर परोक्ष रूप से आश्रित लोगों अथवा रेलवे के ठेकेदारों अथवा उप-ठेकेदारों के पास नियोजित कर्मचारियों की नौकरियां अथवा काम छिन जाने के बारे में प्राक्कलन के लिए कोई अध्ययन शुरु किया है, क्योंकि रेलवे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगारों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे में परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त लोगों पर लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेलवे पर परोक्ष रूप से आश्रित व्यक्तियों पर वैश्विक महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को राज्य सभा में डॉ. सांतनु सेन द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.258 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित **विवरण**।

(क) एवं (ख): रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन के बाद नौकरियां या काम छिन जाने का अनुमान लगाने के लिए मार्च 2020 में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है। बहरहाल, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आर्थिक कार्यकलापों को शीघ्रता से शुरू करने के लिए रेलवे द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं, ताकि ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए ठेकागत कामगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकें, जो निम्नानुसार हैं:

(i) सरकार द्वारा 20.06.2020 को घोषित 125 दिन के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रेलवे ने छह राज्यों अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के चिहिनत जिलों में उक्त अभियान के दौरान 140 परियोजनाओं में 14,14,604 श्रम दिन रोजगार सृजित किए।

(ii) रेलवे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगाए गए ठेकागत कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स के तहत लगाए गए उन कर्मचारियों को मज़ूरी देने/भुगतान करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे, जो कर्मचारी 31.05.2020 तक लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर नहीं आ सके थे।

(iii) ठेकेदारों के लिए नकद राशि बढ़ाने के उपाय भी किए गए थे ताकि कार्य निष्पादन शीघ्र किया जा सके और उनके द्वारा कार्यस्थलों पर लगाए गए ठेकागत कामगारों का काम बढ़ाया जा सके। इन उपायों में कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए चालू ठेकों में कार्य निष्पादन गारंटी रिलीज़ करना, बैंक गारंटी के तहत ठेकेदारों को रेलवे के पास उपलब्ध प्रतिभूति जमा रिलीज़ करना आदि शामिल है।

(ग) और (घ): रेल मंत्रालय ने इस प्रकार का अध्ययन कराने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है क्योंकि संविदागत निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं और इस प्रकार के अध्ययन से वास्तविक लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.258
ANSWERED ON 19.03.2021

IMPACT OF PANDEMIC AND LOCKDOWN ON INDIRECTLY DEPENDENT PERSONS ON RAILWAYS

258. DR. SANTANU SEN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government has undertaken a study to estimate the job loss or work loss post lockdown in March, especially for those who were indirectly dependent on Railways for their livelihood or those who were employees of contractors and sub-contractors of Railways as Railways are one of the biggest source of employment, both direct and indirect,;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, whether Government is planning to take up such study to assess the impact of the lockdown and pandemic on those indirectly employed with Railways, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMERCE & INDUSTRY AND CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF STARRED QUESTION NO.258 BY DR. SANTANU SEN ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 19.03.2021 REGARDING IMPACT OF PANDEMIC AND LOCKDOWN ON INDIRECTLY DEPENDENT PERSONS ON RAILWAYS

(a) & (b): Ministry of Railways has not undertaken any such study to estimate the job loss or work loss post lockdown in March 2020. However, to expeditiously re-start economic activities after lifting of lockdown so as to provide employment opportunities to the contract workers engaged by contractors, Railways took a number of measures as under:

(i) Under the Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan (GKRA) announced by Government on 20.06.2020 for 125 days, Railways generated 14,14,604 mandays employment in 140 projects during the above Abhiyaan in identified Districts across six States, namely, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand and Odisha.

(ii) Instructions were issued to release wages/payment to contractual staff directly engaged by Railways and outsourced staff engaged through contractors, who could not attend duty during lockdown period upto 31.05.2020.

(iii) Measures were also taken to increase the cash flow of contractors so as to expedite execution of works and corresponding increase in engagement of contract workers on work sites by them. Measures include release of Performance Guarantee in the on-going contracts proportionate to progress of work, release of Security Deposit available with Railways to contractors against Bank Guarantee, etc.

(c) & (d): Ministry of Railways has not planned to take up any such study since the contractual works have already been re-started and such study is not likely to provide any tangible benefits.

*****